शब्द–ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
ISSN 2320 – 0871
17 सितम्बर 2014

उत्तर प्रदेश में सामाजिक आन्दोलनों की प्रासंगिकता और उनके प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन

अभिनव दिव्यांशु, नानक चन्द गौतम (शोधार्थी)
इतिहास एवं सभ्यता विभाग
मानविकी और सामाजिक विज्ञान संकाय
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा, उ.प्र., भारत

शोध संक्षेप

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश संतों और राजनीतिज्ञों की जन्मस्थली रहा है, लेकिन सामाजिक असमानता सदियों से उत्तर प्रदेश के विकास में एक विकराल समस्या रही है। प्रस्तुत शोध पत्र में सामाजिक आन्दोलनों द्वारा उत्तर प्रदेश के दलित समाज में आये बदलावों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा कि आजादी के 67 वर्षो के बाद भी उत्तर प्रदेश के दलित सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनैतिक रुप से क्यों सशक्त नहीं हो पाये हैं ? यह जानने की कोशिश भी होगी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के दलितों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन आया है या नहीं।

प्रस्तावना

भारत 28 राज्यों और 7 केन्द्रशासित प्रदेशों का एक संघ हैं जिसमें उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधर पर भारत का सबसे बडा राज्य हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत प्राचीन है। उत्तर प्रदेश सघन आबादी वाले गंगा और यमुना नदी के मैदान में बसा हुआ है जो 23 52' उत्तरी अक्षांश से 30 28' उत्तरी अक्षांश और 84 39 के पूर्वी देशान्तर के दक्षिण के मध्य में स्थित है। यह राज्य 2, 36, 566 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश अनेक महान ऋषि मुनियों और संतों जैसे भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि कबीरदास, रामानन्द, तुलसीदास आदि का तपोभूमि रहा है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने आगरा और अवध को मिलाकर एक प्रान्त बनाया जिसे आगरा और संयुक्त प्रान्त के नाम से जाना जाने लगा। स्वाधीनता के पश्चात्, 1 नवम्बर, 1956 को उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ। भारतीय संसद ने 2002 में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को विभाजित करके उत्तरांचल का निर्माण किया। आधुनिक उत्तर प्रदेश में 78 जिले हैं। उत्तर वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश; मध्य देश के नाम से जाना जाता था और वैदिक काल के कई महान ऋषि मुनियों भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि आदि का उत्तर प्रदेश तपोभूमि रहा है। रामायण और महाभारत की गाथा भी इसी पर आधारित है। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में जैन धर्म

और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति की। अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी और मथुरा विद्याध्ययन के मुख्य केंद्र थे। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश मुस्लिम शासकों के अधीन रहा और हिंदू और मुस्लिमों के सम्पर्क से हिंदू-मुस्लिम संस्कृति का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश का भारतीय इतिहास में महत्तवपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि कबीरदास, रामानन्द, तुलसीदास, सूरदास, राम-कृष्ण आदि संतों और अवतारों का जन्म इसी पावन धरती पर हुआ। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने आगरा और अवध को मिलाकर एक प्रान्त बनाया, जिसे आगरा और संयुक्त प्रान्त के नाम से जाना जाने लगा।

आधुनिक काल में उत्तर प्रदेश, स्वामी अछूतानन्द, लालबहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, बी.पी. मौर्य, चौधरी चरणसिंह, विश्वनाथ प्रतापसिंह, राजीव गांधी, चंद्रशेखर आदि समाज सुधारकों और राजनीतिज्ञों की जन्म स्थली रहा है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार से भारत का सबसे बडा राज्य है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आगरा, अलीगढ, वाराणसी, अयोध्या और मथुरा आदि उत्तर प्रदेश के महत्तवपूर्ण शहर है जो अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान आदि राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है। भारतीय संसद ने 2002 में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को विभाजित करके उत्तरांचल का निर्माण किया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 78 जिले हैं। जनगणना 2001 के अनुसार, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16 करोड़ है, जिसमें दलितों की जनसंख्या 3 करोड़ 57 लाख है। यह राज्य 2, 36, 566 वर्ग किलो मीटर में फैला हुआ है। आधुनिक उत्तर प्रदेश में दलित कौन हैं, अगर मन से मनन करें तो जाति से जुड़े हुए प्रश्न स्वतः ही खुल जायेंगे। जाटव, पासी, धोबी, कोरी, वाल्मीकि, खटीक, बहेरा, कोल, गौतम आदि 66 उपजातियों में दलित समाज विभाजित है, जिन्हें संविधान में अनुसूचित जाति और जन जाति का दर्जा दिया गया है।

दलित चेतना का स्वरुप और विकास

दलित गरीब और अस्पृश्य तबके की पहचान का शब्द है, जिसे संवैधानिक एवं प्रशासनिक भाषा में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 341;1, 2 में चिह्नित है। दलित शब्द का अर्थ आमतौर पर जनसंख्या के उस अपमानित, शोषित, वंचित, और उत्पीड़ित वर्ग से है जो परम्परागत आधार पर सदियों से अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकारों से वंचित रहा है। दलित समाज ने अपने शोषण, उत्पीड़न और मानव अधिकार प्राप्त करने हेतु जो निरन्तर प्रयास किये उनसे दलित चेतना का निर्माण हुआ।

हरबर्ट मार्कुस के शब्दों में कहें तो दलित चेतना एक प्रति-सांस्कृतिक चेतना है, जिसका उद्देश्य पुरातन मान्यताओं पर आधारित सामाजिक और सांस्कृतिक तिलिस्म को तोड़ना है, लेकिन जीवन मूल्यों की खोज एवं मानवीय सरोकार दलित चेतना की मूलधारा में अन्तर्निहित है। दलित चेतना सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अधिकारों एंव सुरक्षा की मांग है, जो दलित पीड़ा एवं अंतर्द्वन्द्व को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। कोई भी आन्दोलन अचानक खड़ा नहीं होता अपितु उसके लिए कुछ घटनाएं उसकी पृष्ठभूमि तैयार

करती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दलित चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान करने में विभिन्न्न सामाजिक आन्दोलनों का योगदान रहा है और उन्होंने दलित समाज को न्याय एवं मानवाधिकार प्राप्त करने हेतु जो निरन्तर प्रयास किये, उनसे दलित चेतना का निर्माण हुआ। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान विभिन्न समुदायों के द्वारा ब्रह्म समाज आन्दोलन, आर्य समाज आन्दोलन, शुद्धि आन्दोलन आदि हिन्दू आन्दोलन, अलीगढ़ आन्दोलन, सत्यशोधक समाज आन्दोलन, हरिजन आन्दोलन, ब्राहाणविरोधी आन्दोलन, आत्मसम्मान आन्दोलन, श्री नारायण धर्म परिपालन आन्दोलन, समता संघ, शिड्यूल कास्ट आफ फेडरेशन, दलित वर्ग संघ आदि सामाजिक आन्दोलन चलाये जिन्होंने शैक्षणिक और सामाजिक परिवर्तन करके दलित चेतना को बढ़ने का मौका प्रदान किया जिससे दलित समाज वर्तमान में शोषण और उत्पीडन के विरुद्ध न्याय की मांग करने लगा है। डॉ.अम्बेडकर ने दलित समाज को संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय दिलाने हेतु जो आवाज उठाई उससे उत्तर प्रदेश में दलित चेतना का निर्माण हुआ।

सामाजिक आन्दोलन और दलित चेतना

यह सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश के दलितों के उत्थान में सामाजिक आन्दोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहीं है और दलित चेतना को प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में विभिन्न सामाजिक आन्दोलनों का प्रादुर्भाव हुआ जैसे- जाटव आन्दोलन, बैरवा आन्दोलन, रिपब्लिकन सेना, आदि हिन्दू आन्दोलन, दलित सेना, भीम सेना, रविदासी आन्दोलन, कबीरपंथी आन्दोलन, हरिजन आन्दोलन, दलित पैंथर आन्दोलन, पालकी संघर्ष आन्दोलन, मिसरखिया आन्दोलन, बामसेपफ, डी.एस-4 और बहुजन दल आदि का प्रादुर्भाव हुआ लेकिन ये आन्दोलन कुछ तो तोड़ दिये गये और कुछ खरीद लिये गये। इतिहासकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक आन्दोलनों का प्रमुख उद्देश्य जांति पांति के बंधन को तोडना, अस्पृश्यता के अभिशाप को समाप्त करके भाईचारे में रूपान्तरित करना एवं सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना रहा हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के दलितों के विकास के मार्ग में जाति व्यवस्था और अशिक्षा सबसे विरल चुनौती है।

उत्तर प्रदेश के सामाजिक इतिहास में अस्पृश्यता का महत्तवपूर्ण स्थान रहा है, जो वैदिक काल से अपनी पैठ बनाये हुए है क्योंकि इसकी नींव हिन्दू समाज की सामाजिक और धर्मिक मान्यताओं पर टिकी हुई है, लेकिन अस्पृश्यता की अवधरणा जिस तरह उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई थी वर्तमान में उसका भौतिक स्वरूप बदल चुका है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ बदलाव अवश्य आया है लेकिन खाने-पीने की छुआछूत सवर्ण ही नहीं करते हैं, दलितों में भी अभिशप्त हैं। इसमें कोई संदेह नही है कि असमानता हर समाज और युग में किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है।

लोहिया ने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया एवं दलितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए जीवनपर्यन्त संघर्ष करते रहे और उनका कहना था कि ब्राहमणवाद तो बुरा है, लेकिन ब्राहमण विरोध उससे भी बुरा है। वे उत्तर प्रदेश के दलितों के सार्वभौमिक विकास के लिए निरन्तर प्रयास करते रहे। उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया के नेता बी.पी.मौर्य ने सामाजिक आन्दोलन चलाकर हिन्दुत्व और

साम्प्रदायिक शक्तियों का विरोध किया और जयप्रकाश नारायण के नेत्तृव में चलाये गये जन आन्दोलन संपूर्ण क्रांति, दलितों को आत्मसम्मान दिलाने, समतामूलक समाज बनाने, जाति उन्मूलक समाज बनाने, विभाजित समाज को जोडने, दलितों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा में सुधारों को नई दिशा दी। कांशीराम ने बामसेफ, दलित शोषित संघर्ष समिति और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके दलित समाज में राजनैतिक चेतना का संचार किया। मायावती ने दलित उत्थान और विकास के लिए कांशीराम आवास योजना, महामाया आशीर्वाद बालिका योजना और महामाया आवास योजना आदि योजनाओं को प्रारम्भ करके दलितों का सार्वभौमिक विकास करने हेतु अथक संघर्ष किया।

उत्तर प्रदेश में सतत् दलित चेतना में सामाजिक आन्दोलनों के योगदानों के परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो डॉ.अम्बेडकर ने दलितों के सामाजिक और राजनैतिक ढाँचे में सुधार लाने हेतु जो सिद्धांत और तरीके अपनाये उनसे उत्तर प्रदेश में आधुनिक दलित चेतना का निर्माण हुआ। दुर्खीम मानते हैं कि चेतना झरने के समान बहती रहती है। उत्तर प्रदेश में दलित चेतना पर गंभीरतापूर्वक चर्चाएँ नहीं होती है। दलित चेतना एक महत्तवपूर्ण मुद्दा है, ताकि हम समझ सकें उत्तर प्रदेश में दलितों के उत्पीडन का आधर क्या हैं?

डॉ.अम्बेडकर ने दलित उपजातियों का एकीकरण और दलित समाज को हिन्दू धर्म से बचाने के लिए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 5 लाख महारों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया, क्योंकि बौद्ध धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा पर आधारित है। बौद्ध धर्म परिवर्तन करने वालों की कोई जाति नहीं होती है। जातिभेद और वर्णभेद को मिटाना आसान नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में दलित समाज की मान्यताएं भी परिवर्तित होने लगी हैं।

स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान राजनैतिक आजादी के साथ 26 जनवरी 1950 को भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था और किसी भी वर्ग और समुदाय के साथ जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधर पर भेदभाव नहीं करने का संकल्प भी लिया गया था। भारतीय समाज में अभिशप्त पिछड़ापन और अस्पृश्यता की समस्या को समाप्त करने का वायदा भी किया गया था। उत्तर प्रदेश ने आजादी के 65 वर्ष पूरे कर लिये हैं लेकिन वर्तमान में भी अस्पृश्यता अपनी पकड़ बनाये हुए हैं। उत्तर प्रदेश के दलितों के विकास की जो जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई थी, वह कार्य पूरी तरह ईमानदारी के साथ नहीं किया गया है और उत्तर प्रदेश का सवर्ण समाज यह भी समझ पाने में नाकामयाब ही रहा है कि शताब्दियों से शोषित समाज को ऊपर उठाने का उत्तरदायित्व समाज पर है।

समाजशास्त्रियों और इतिहासकारों का मानना है कि सामाजिक आन्दोलन अहिंसात्मक और संवैधानिक साधन है, जो सामाजिक प्रतिकारों, शोषण और परिवर्तन के प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश में सामाजिक आन्दोलनों का मुख्य उद्देश्य जांति-पांति के बंधन को तोडना, अस्पृश्यता के अभिशाप को समाप्त करके भाईचारे में रूपान्तरित करना और राजनीतिक परिवर्तन लाना रहा है क्योंकि अस्पृश्यता उत्तर प्रदेश के दलितों के विकास के मार्ग में सबसे विकराल चुनौती है। सामाजिक

आन्दोलन सांस्कृतिकरण और दलितीकरण के केन्द्र रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में दलित चेतना और सामाजिक आन्दोलनों के वास्तविक स्रोत डॉ.अम्बेडकर ही हैं। रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया, दलित पैंथर, दलित सेना, भीम सेना, आदि हिंदू सभा,, जाटव आन्दोलन, बामसेपफ, दलित शोषित संघर्ष समिति और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और बौद्धिक स्तर पर चेतना और समानता लाने हेतु आदि मुद्दे इन आन्दोलनों के माध्यम से उठाये जाते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि दलित चेतना में निरंतर वृद्वि हो रही है। अगर आधुनिक उत्तर प्रदेश में दलित चेतना का अवलोकन करें तो यह विदित होता है कि उत्तर प्रदेश में दलितों की साक्षरता दर 1961 में 7.14 प्रतिशत से बढ़कर 1971 में 10.2 प्रतिशत, 1981 में 15 प्रतिशत, 1991 में 27 प्रतिशत, 2001 में 47 प्रतिशत वृद्वि हुई है। सन् 1994 में, उत्तर प्रदेश में 500 आई.ए.एस संवर्ग में से 137 अनुसूचित जाति के अफसर और अन्य पिछडे वर्गो के केवल सात थे। ब्राह्मणों और कायस्थों के बाद दलित जाति के अफसर सबसे बड़ी संख्या में थे। उत्तर प्रदेश में मायावती का चार बार मुख्यमंत्री बनना दलित चेतना का साक्षात उदाहरण हैं, लेकिन वर्तमान में भी दलित समुदाय समाज में सामाजिक समानता प्राप्त करने में नाकामयाब ही दिखाई पडता है। मायावती के द्वारा उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर की 15000 हजार मूर्तियां लगवाना, डॉ.अम्बेडकर विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, एकलव्य स्टेडियम, बुद्ध सर्किट, दलित प्रेरणा स्थल पार्क, पंचशील, महामाया, प्रबुद्ध नगर जिलों की स्थापना करना दलित चेतना के ज्वलंत उदाहरण हैं। लेकिन इंटरनेट के युग में भी अस्पृश्यता अपनी पैठ बनाये हुए हैं। लेकिन यह सत्य है कि कुछ वर्षो के अंतर्गत दलितों की सामाजिक और आर्थिक हैसियत में परिवर्तन अवश्य हुआ है।

सन् 1925 में स्वामी अछूतानन्द ने कानपुर में आदि हिंदू आन्दोलन चलाकर दलितों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने गवर्नर को अस्पृश्यों की समाज में दयनीय दशा और प्रतिदिन उनके साथ हो रहे शोषण और अन्याय से अवगत कराया। दलित सम्मान आंदोलन का केंद्र लखनऊ रहा जिसमें डॉ.प्रशांत का नाम सर्वोपरि है। दलित सम्मान आन्दोलन के आर्कषण के मुख्य केंद्र सीतापुर, उन्नाव, हरिदोई, रायबरेली, आगरा, अलीगढ़ रहे और इन जिलों में दलितों के साथ होने वाले शोषणों और अन्यायों के विरुद्ध सम्मेलन आयोजित हुए। सिड्यूल कास्ट आफ फेडरेशन ने उत्तर प्रदेश के दलितों के उत्थान में विशेष रुप से भूमिका निभाई।

पालकी सम्मान संघर्ष आन्दोलन का केंद्र लखनऊ था। सन् 1957 में, उत्तर प्रदेश के मिसरिख जिले में बौद्ध समारोह आयोजित हुआ जिसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ कि मिसरिख के मेले में दलित जातीय साधू-संतों द्वारा भी अपने जुलूस में संत रविदास की पालकी निकाली जाए। सवर्ण समाज के लोगों ने दलित समाज के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने दलितों के साथ मारपीट की। अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध आन्दोलन चलाया और प्रण लिया कि अगर साधू सन्यासियों की पालकी चलेगी तो हमारी भी रैदास की पालकी चलेगी और यह उस सम्मान संघर्ष का ही परिणाम है कि मिसरिख के मेले में दलितों के पंडाल लगते हैं और दलित संतों की पालकी भी निकाली जाती है। यह आन्दोलन

दलितों का ऐतिहासिक सम्मान संघर्ष आन्दोलन था। इस आन्दोलन की विशेष उपलब्धि घुंघतेर गांव में 3 मई 1984 को बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित करना और बुद्ध विहार का निर्माण करना रहा है।

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में दलितों के उत्थान में दलित सम्मान आंदोलन की मुख्य भूमिका रही है। जेरी गांव, जनहिया तहसील, संड़ीला तहसील के दलितों साथ होने वाले शोषण और अन्यायों के विरुद्ध अभियान चलाया और अराजकतावादी तत्वों को जेल भेजकर दलितों को न्याय दिलाने में बहुत बडी भूमिका निभाई। खीरी लखीमपुर में दलित सम्मान का मुख्य कार्य रैदास मंदिर धर्मशाला और बुद्ध विहार की स्थापना था और यही कारण है कि 2001 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से अधिक इस जिले में बौद्धों की संख्या सर्वाधिक है। वाराणसी क्षेत्र भी सामाजिक आन्दोलनों से अछूता नहीं रह सका। सन् 1980 में, बाबू जगजीवन राम को वाराणसी में एक मूर्ति स्थापित कराने के लिए आमंत्रित किया। बाबू जगजीवनराम दलित थे इसीलिए बनारस के पुजारियों ने यह कहकर विरोध किया कि अछूत जगजीवनराम के छूने से मूर्ति अशुद्ध हो गई। अस्पृश्यता और जातीय भेदभाव के खिलाफ सामाजिक आन्दोलन की असफलताओं ने राजनैतिक आन्दोलन की आधारशिला रखी।

सामाजिक और राजनीतिक रूप से स्वाधीन भारत में जयप्रकाश नारायण के नेत्तृव में चलाये गये जन आन्दोलन; संपूर्ण क्रांति और लोहिया के पिछडे पावैं सौ में साँठ के साथ समग्रता से कांशीराम ने दलितों को आत्मसम्मान दिलाने, समतामूलक समाज बनाने, जाति उन्मूलक समाज बनाने, विभाजित समाज को जोडने, बामसेफ, दलित शोषित संघर्ष समिति और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके दलितों की सामाजिक, आर्थिक, धर्मिक और राजनीतिक दशा में सुधारों को नई दिशा दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी में पेरियार मेला लगाकर दलितों में अपने अधिकारों के प्रति सामाजिक, धर्मिक, राजनैतिक चेतना का संचार किया। कांशीराम ने दलित समाज में चेतना लाने के लिए आह्वान किया कि 'जाति तोड़ो', 'समाज जोड़ो,' 'जातियों की चीनी दीवार नष्ट करो' और 'भाईचारे के पुल बनाओं'।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश के दलितों के उत्थान में सामाजिक आन्दोलनों का विशेष योगदान रहा है लेकिन वर्तमान में सामाजिक आन्दोलन दलितों के शोषण और उत्पीडन की घटनाओं को जनमानस के पटल पर रखने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। दलित समाज की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनैतिक दशा में परिवर्तन अवश्य आया है लेकिन जो लक्ष्य दिया गया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दलितों के उत्थान एवं विकास के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी योजनाएं क्रियान्वित की गई है लेकिन दलितों का पूर्ण रुप से विकास नहीं हो पाया है इसीलिए सरकार को शोषितों और वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए सर्वेक्षण कराके उनकी दशा में सुधार करने हेतु योजनाओं का क्रियान्वन किया जाए जिससे दलित समाज देश के विकास के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकें।

संदर्भ ग्रन्थ

1 पासवान, डॉ.चंद्रशेखर, बौद्ध धर्म और आधुनिक दलित चेतना, नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय, 1998

2 भारती, कंवल, मायावती और दलित आन्दोलन, नई दिल्ली: रमणिका फाउंडेशन, 2004

3 गुप्ता, रमणिका, दलित चेतना-सोच, बिहारः नवलेखन

4 गुप्ता, रमणिका, दलित चेतना-सोच, बिहारः नवलेखन

5 लिंबाले, शरण कुमार, दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्रा, नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन, 1997, पृष्ठ-70

6 आर्य, लाल, दलित समाजः आज की चुनौतियां, नई दिल्ली: प्रकाशन संस्थान, पृष्ठ- 21

7 कीर, धंनजय, डॉ.अम्बेडकर का जीवन और उद्देश्य, प्रथम संस्करण, दिल्ली: पोपुलर प्रकाशन, 1990

8 दुबे, अभय कुमार, आधुनिकता के आईने में दलित आन्दोलन, नई दिल्लीः वाणी प्रकाशन, 2008.

9 देसाई, ए.आर., भारतीय राष्ट्रवाद का सामाजिक पृष्ठभूमि, नई दिल्लीः मैकमिलन प्रकाशन, 1988

10 नैमिशराय, मोहनदास, डॉ.अम्बेडकर और मार्टिन लूथर किंग का जीवन संघर्ष, नई दिल्लीः नीलकंठ प्रकाशन, 2000

11 चंचरीक, कन्हयालाल, आधुनिक भारत का दलित आंदोलन, नई दिल्लीः दया पब्लिशर, 2006

12 तेलतुमड़े आनन्द, सत्ता, समाज और दलित, दिल्लीः एम.एस.पब्लिशर्स, 2011s